आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 25.10.2023 से 29.10.2023)

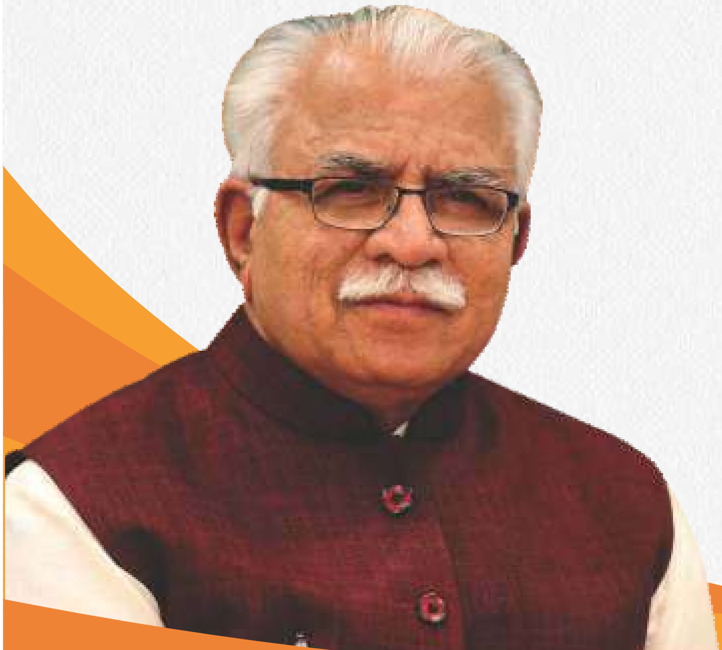

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम

(दिनांक 25.10.2023)

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी आज रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि वर्ष 2022 से 2047 तक देश में आजादी का अमृत काल चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना है। इस अमृतकाल में देश की आजादी के लाखों वीर बलिदानियों को याद किया जा रहा है। हर घर तिरंगा के बाद अब मेरी माटी–मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को पंच प्रण की शपथ भी दिलवाई जो दृढ़ता से हम सभी के जीवन का हिस्सा बनेगी। उन्होंने विख्यात कवि प्रदीप की लिखी **पंक्ति– आओ बच्चों तुम्हे दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की– भी दोहराई।**

उन्होंने कहा कि आज यहां प्रदेशभर के कौने–कौने से 242 कलश में हरियाणा की पवित्र माटी को स्वयंसेवको द्वारा लाया गया है जिसे 29 अक्तूबर को दिल्ली ले जाया जाएगा। पूरे देशभर से 75000 कलश देश की पवित्र माटी को लेकर दिल्ली पहुंचेगे और जहां अमृतकाल के स्मारक के रूप में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि देश के लगभग 7 लाख गावं व शहरों के घर–घर से लाई जा रही यह पवित्र माटी जब दिल्ली पहुंचेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी स्वयंसेवकों को शपथ दिलाएंगे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी

(दिनांक 25.10.2023)

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले परियोजनाओं को आज यहां प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 19 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 30 नई परियोजनाएं 6 जिलों यमुनानगर, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, हिसार और जींद में तथा जिला यमुनानगर, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और नूंह के विभिन्न गांवों में क्षेत्र की जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए 14 ट्यूबवेलों की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

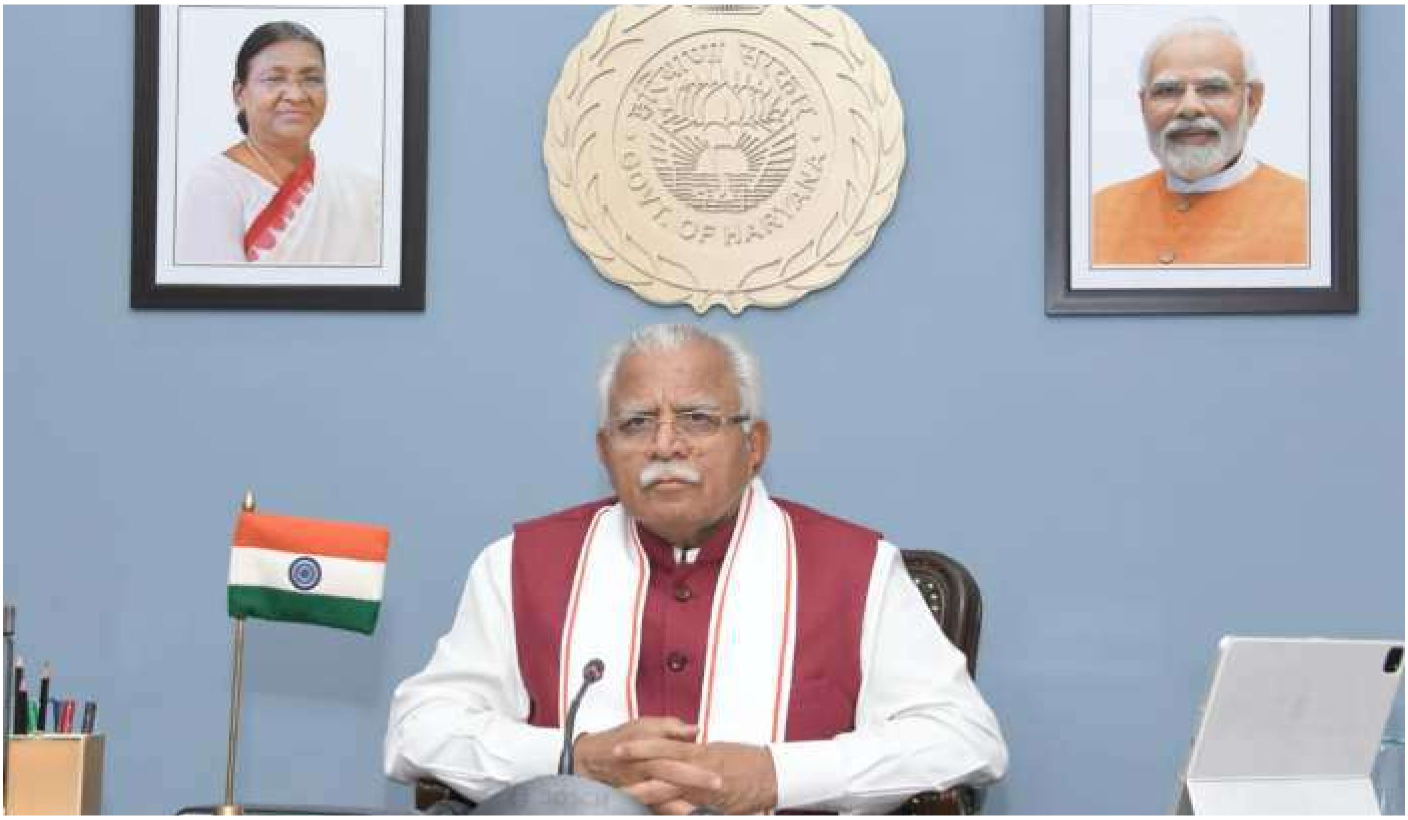

डायल 112 से अब महिलाओं की यात्रा होगी और भी सुरक्षित

(दिनांक 25.10.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी के महिला सुरक्षा के विजन और दिशानिर्देशों के अनुसारपुलिस महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसके दौरान हरियाणा–112 के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस विभाग अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही महिला सुरक्षा को लेकर और अधिक अपडेटेड व हाइटेक होने जा रहा है। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। महिला सुरक्षा पुलिस विभाग की प्राथमिकताओं में से एक हैं। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में महिलाएं घरों से बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। इसी कड़ी में **हरियाणा 112 अब महिला यात्रियों के लिए 'सेफ जर्नी' अर्थात् 'सुरक्षित यात्रा' का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। इसके तहत अब महिलाएं 112 डायल करके अपने आप को रजिस्टर करते हुए एडवांस में अपनी यात्रा संबंधी जानकारी हरियाणा 112 की टीम के साथ शेयर कर सकेंगी। इसके लिए महिलाएं अपनी डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर, प्लेस आफ डिपार्चर, प्लेस ऑफ़ अराइवल, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ़ डिपार्चर व अराइवल आदि जानकारी सांझा करेगी।** इसके बाद, हरियाणा 112 की टीम द्वारा महिला के संपर्क में रहेगी। इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लोकेशन ट्रैक की जाती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे–ओला, उबर तथा ऑटो आदि पर भी हरियाणा पुलिस द्वारा स्टिकर लगाए जा रहे हैं जिसमें ऑटो चालक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का नंबर आदि सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।

पीएम श्री स्कूलों का लोकार्पण समारोह

(दिनांक 25.10.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बुधवार को रोहतक स्थित महर्षि दयांनद विश्वविद्यालय के टैगौर सभागार में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पीएम श्री स्कूलों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर कहा कि प्रदेश में शुरू किए गए 4000 प्ले वे स्कूल को अब बाल वाटिका स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सरकार द्वारा इतने ही और स्कूल भी भविष्य में शुरू किए जाएंगे। बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को भी इन स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर में और सुधार के लिए **प्रथम चरण में 124 पीएम श्री**

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्कूलों का नए सत्र से शुभारंभ होगा तथा दूसरे चरण में 128 स्कूलों के शुभारंभ के साथ ही इन स्कूलों की संख्या 252 हो जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रथम चरण में प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों का लोकार्पण करते हुए प्रदेश को सौगात दी।

ये शिक्षा ही है जो युवा पीढ़ी और देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। देश जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, उसे हासिल करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार, व्यवहार के साथ–साथ अपने इतिहास व संस्कृति की जानकारी होना तथा इनसे लगावा होना भी अनिवार्य है।

उन्होंने पीएम श्री स्कूलों के संदर्भ में कहा कि इस योजना के तहत विद्यालयों को सम्मान देने के साथ–साथ विद्यालयों से जुड़े व्यक्तियों को भी मान सम्मान दिया गया है। उन्होंने अध्यापकों का आहवान किया कि वे विद्यार्थियों के स्तर को सुधारने के लिए ज्ञानवर्धक और संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान करवाएं।

पीएम श्री विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21 वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है और हम उन पलों का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण की नींव रख रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश देश में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है।

प्रदेश में पारदर्शी शिक्षक भर्ती, ऑनलाईन ट्रांसफर नीति के सराहनीय कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल व तकनीक आधारित शिक्षा तथा मातृ भाषा को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने एशियन खेलों में हरियाणा के खिलाडियों द्वारा पदक प्राप्त किए की सराहना की।

जिला रोहतक की दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित अर्पण व श्रवण संस्थाओं का दौरा

(दिनांक 25.10.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला रैडक्रास सोसायटी, रोहतक द्वारा संचालित की जा रही अर्पण व श्रवण संस्थाओं का दौरा किया तथा इन संस्थाओं में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की प्रशंसा की। उन्होंने इन संस्थाओं का दौरा कर परिसर में पौधारोपण किया तथा मिठाईयां भी वितरित की। जिला रैडक्रास सोसायटी द्वारा मानसिक रूप से विकलांगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने दोनो संस्थाओं को 5–5 लाख रुपए ग्रांट देने की भी घोषणा की।

सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां

(दिनांक 26.10.2023)

प्रभाव: प्रदेश सरकार के आज 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां प्रेस वार्ता को संबोधित कर कहा 9 वर्ष पहले व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना की गई थी, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। विगत 9 सालों का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन, सबका साथ–सबका विकास –सबका विश्वास–सबका प्रयास, संवेदनशील व पारदर्शी प्रशासन और अंत्योदय उत्थान का साक्षी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है। भाई–भतीजावाद व क्षेत्रवाद को खत्म कर प्रदेश का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के विजन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर

साप्ताहिक सूचना पत्र

सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए प्रदेश में समाज कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात किया है। आज हमारे सुधार के संकल्प के परिणाम आ रहे हैं। अब सरकारी सेवाओं व योजनाओं के लाभ घर बैठे मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी मुख्य तौर पर बात की जाए तो 9 सालों में 9 बड़े काम हमने किए हैं।

परिवार पहचान पत्र बनाकर प्रभावी तरीके से घर बैठे 45 लाख परिवारों को 397 योजनाओं व सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने बी.पी.एल. की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर अधिक से अधिक परिवारों को योजनाओं के लाभ के दायरे में लेकर आए हैं। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,750 रुपये मासिक देश में सर्वाधिक मिल रही है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलतापूर्वक लागू करके जन्म के समय लिंगानुपात जो वर्ष 2014 में 871 था, वो आज सुधरकर 932 (सितम्बर, 2023) तक पहुंचा है।

इनके अलावा, मेरी फसल–मेरा ब्योरा पोर्टल किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। सरकार ने डी.बी.टी. के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 85 हजार करोड़ रुपये डाले हैं।

चिरायु/आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा के भीतर 25 लाख से अधिक परिवारों को मालिकाना हक देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने सुशासन की नई पहलों से प्रदेश के नागरिकों में यह विश्वास पैदा किया है कि सरकार उनकी है और वे सरकार के हैं। हमने अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाओं को ऑनलाइन किया है। उन्होंने कहा कि हमने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के

साप्ताहिक सूचना पत्र

माध्यम से 36 विभागों की 404 सेवाएं ऑनलाइन की और 8,93,086 शिकायतों का निपटान किया गया। नागरिकों को हर समय पुलिस सहायता मुहैया करवाने के लिए हरियाणा आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा डायल–112 शुरू की और 19,28,563 कॉल्स पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ई–ऑफिस की अवधारणा को क्रियान्वित करके सरकारी कामकाज में तेजी लाने का काम किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं, इसलिए किसानों को समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान कल्याण के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। एम.एस.पी. पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के 19.82 लाख किसानों के खातों में 4287.19 करोड़ रुपये की राशि पहुंची है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 27.22 लाख किसानों को 7600 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिया गया है।

इसके अलावा, जल संरक्षण के लिए शुरू की गई मेरा पानी–मेरी विरासत योजना के तहत 71,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोई गई और योजना के तहत 7,000 रुपये

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रति एकड़ की दर से किसानों को 118 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा व बागवानी किसानों के खातों में 750 करोड़ रुपये डाले गए।

ख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत अति गरीब 50 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण मुहैया करवाया गया। आयुष्मान भारत–चिरायु योजना के तहत 86 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 32 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच व 1.70 करोड़ टैस्ट निशुल्क किये गये। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी–हमारी बेटी योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की 4.30 लाख लड़कियों को जन्म पर 21,000 रुपये प्रति बेटी के अनुसार राशि दी गई।

हमारी सरकार ने ग्राम विकास पर फोकस करते हुए विभिन्न निर्णय लिए हैं। पंचायतों को सशक्त किया गया है, ताकि वे अपने स्तर पर विकास कार्य करवा सकें। इसके लिए सरकार ने हर साल का निश्चित बजट पंचायतों को देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है और हमारी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए को 8 प्रतिशत आरक्षण दिया है।

उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से सरकार नारनौल में 700 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से 886 एकड़ क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित कर रही है। आई.एम.टी खरखौदा, सोनीपत में मारुति सुजुकी द्वारा 800 एकड़ तथा सुजुकी द्वारा 100 एकड भूमि पर उद्योग स्थापित किया गया है।

पी.एम.गति शक्ति योजना के तहत प्रदेश में 6 परियोजनाओं में से 3 परियोजनाएं मंजूर हुई हैं। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क व हिसार में ब्लक ड्रग्स पार्क स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा, पदमा स्कीम (वन ब्लॉक–वन

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रोडक्ट) के तहत 143 ब्लॉकों में क्लस्टर आधार पर प्रथम चरण में 40 क्लस्टर्स में विकास परियोजनाएं शुरू की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों के कल्याणार्थ उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग और सेंधमारी के मामले में नुकसान के लिए 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक का बीमा कवर और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3.86 लाख पंजीकृत व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा है।

वर्तमान में 8 राजमार्गों का कार्य पूर्ण व 12 का प्रगति पर है। दिल्ली के चारों तरफ यातायात को सुगम करने के लिए कुंडली–मानेसर–पलवल और कुंडली–गाजियाबाद–पलवल एक्सप्रेस–वे बनाए और उन पर यातायात सुगमता से जारी है। रोहतक शहर में देश की पहली एलिवेटिड रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण और

कुरुक्षेत्र में इसी परियोजना पर कार्य शुरू हो गया। कैथल में एलिविटिड लाइन के लिए सर्वे किया जा रहा है। 2577 करोड़ रुपये की लागत से 62 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 50 पुलों का कार्य प्रगति पर है। वाई.एम.सी.ए. चौक से बल्लभगढ़, बहादुरगढ़–मुंडका (दिल्ली), बदरपुर–मुजेसर (वाईएमसीए चौक) व सिकंदरपुर स्टेशन से सेक्टर–56 तक मैट्रो सेवा शुरू हो गई है।

प्रदेशवासियों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने

साप्ताहिक सूचना पत्र

कई कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। वर्ष 2014 में प्रदेश में 1 मेडिकल विश्वविद्यालय था और आज 2 विश्वविद्यालय संचालित हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 में 6 थी, जो आज बढ़कर 15 हो गई है और एमबीबीएस सीटों की संख्या 700 (वर्ष 2014 में) थी, जो आज 2185 तक पहुंच गई है। देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने व रोजगारपरक शिक्षा के लिए कई पहलें की हैं।

बचपन से ही खेल–खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए 4000 प्ले वे स्कूल खोले हैं, जिन्हें अब बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा।

हमने मिशन मैरिट शुरू किया और **पारदर्शिता के आधार पर 1.10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और 60 हजार नौकरियां और देने की तैयारी है।** भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने ग्रुप–सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का काम किया है।

सक्षम युवा योजना के तहत 4 लाख सक्षम युवाओं को 9000 रुपये प्रतिमाह तक दिया गया और 2504 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ता व मानदेय के रूप में वितरित किए गए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बारहवीं, स्नातक व समकक्ष युवाओं को 3,000 रुपये मासिक तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

आज हरियाणा का युवा अपने खेल प्रतिभा के दम पर न केवल देश में अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। युवाओं का खेलों के प्रति रूझान बढ़ा है। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेलों में 40 प्रतिशत मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है, वहीं सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए अलग

से सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण का गठन किया है और अभी तक अनुकंपा के आधार पर शहीद सैनिकों के 367 आश्रितों को सरकारी नौकरी दी है।

ईस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी दिपावली त्यौहार के शुभ अवसर से पहले बड़ा तोहफा देते हुए नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर और अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्तूबर, 2023 से दिया जाएगा।

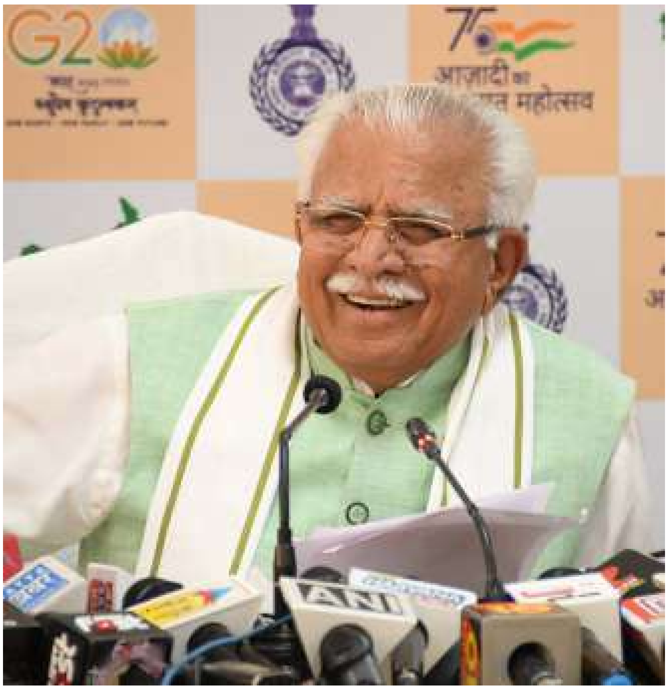

इसके अलावा, उन्होंने हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों व आपातकालीन पीड़ितों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने की घोषणा की।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी दिवाली तोहफा देते हुए डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आज परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 42,431 लोगों की वृद्धावस्था सम्मान पेंशन बनाई गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता के दौरान प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा इस तरह की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य **75 वर्ष से अधिक पुराने स्वस्थ वृक्षों का संरक्षण है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 3,810 वृक्षों को पेंशन देने की विधिवत शुरुआत की।** योजना के तहत इन सभी वृक्षों को सालाना 2750

रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी के घर के आंगन में 75 वर्ष या उससे अधिक पुराना पेड़ है, तो वह अपने संबंधित जिले के वन विभाग के कार्यालय में जाकर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा और सभी शर्तों के सत्यापन के बाद लाभार्थी को पेंशन दी जाएगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार **10 जिलों की 190 कॉलोनियों को नियमित करने की बड़ी घोषणा की है।** इन कॉलोनियों के समग्र विकास के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि नियमित की जा रही 190 कॉलोनियों में से 100 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, शेष 90 शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में हैं। आज इन कॉलोनियों के नियमित करने की घोषणा के साथ ही इस वर्ष कुल 594 कॉलोनियों का

सफलतापूर्वक नियमितीकरण किया जा चुका है।

एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्होंने एक पत्रकार को बताते हुए कहा की **राज्य राजमार्गों पर स्थित छः टोल प्लाजा को बंद करने की घोषणा की है।** इस कदम से आम जनता को भारी राहत मिलने वाली है। इन टोल प्लाजा के बंद होने से जनता को सालाना 13.50 करोड़ रुपये की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इन टोल प्लाजा को बंद करने का निर्णय आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की मांगों को देखते हुए लिया गया है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

महर्षि वाल्मीकि जयंती

(दिनांक 28.10.2023)

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती अवसर पर पंचकूला में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा क्लास वन और टू अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर सफाई कर्मियों को दीवाली व हरियाणा दिवस का तोहफा देते हुए उनके लिए अनेक घोषणाएं की। **इनमें शहरी सफाई कर्मियों का 16 हजार रुपये से 17 हजार रुपये मासिक मानदेय, ग्रामीण सफाई कर्मियों का 14 हजार रुपये से 15 हजार रुपये मासिक मानदेय, कस्सी, तसला व अन्य औजार के लिए 2 हजार रुपये वार्षिक तथा धुलाई भत्ता एक हजार रुपये करने की घोषणा शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सफाई कर्मचारियों की संख्या 6 है,**

वहां 8 की जाएगी और जहां 8 है वहां 10 की जाएगी।

सब लोग आगे बढ़ें, किसी के साथ भेदभाव न हो, समान भाव से हम गरीब व अंत्योदय परिवारों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति के उत्थान में लगे हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा सांसद श्री कृष्ण लाल पवार की मांग पर जीटी रोड पर घोषणा करते हुए कहा कि पिपली के ट्रांस्पोर्ट नगर में 3 एकड़ जमीन के एक क्षेत्र में गुरु रविदास की 25 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी और यह 20 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाई जाएगी। शेष भूमि में प्रशासनिक ट्रस्ट, छात्रावास व शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे।

बीपीएल कार्ड लाभ पात्रों की आय सीमा को एक लाख 20 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये किया गया है, इससे लगभग 12.50 से अधिक नये राशन कार्ड बने हैं। आय सीमा एक लाख 80 हजार रुपये करने से आयुष्मान भारत, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों की संख्या 37–38 लाख परिवार हो गई है। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में भी 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया गया है, इसमें 1500 रुपये का प्रीमियम सरकार देगी और 1500 रुपये मात्र प्रीमियम लाभार्थी को देना होगा।

उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका हक है, उसे हक मिलेगा।

युवाओं से विशेष चर्चा

(दिनांक 28.10.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहां सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के 1 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले युवाओं से संवाद कर कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है, ताकि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और हरियाणा आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि राज्य

सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मैरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची–पर्ची के 1 लाख 10 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस वर्ष 60 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 41 हजार 217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों से ज्यादा वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां हुई हैं। उन्होंने आंकड़ा साझा करते हुए बताया कि वर्ष 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी।

2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी। **जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से**

साप्ताहिक सूचना पत्र

2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी है, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

इसके लिए हमने सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपये वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। **इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 50 हजार लोगों को अंत्योदय मेलों में मदद मिली है।**

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने वालों और रोजगार चाहने वालों को सांझा मंच उपलब्ध करवाया गया है। राज्य सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गये हैं तथा 1 लाख 4 हजार 114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, युवाओं को नौकरी के लिए बार–बार आवेदन करने व फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। बार–बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

इसके लिए सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया है। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने बीड़ा उठाया है कि युवाओं को कौशल विकास व गुणवत्तापरक शिक्षा देकर इतना सशक्त बनाया जाए कि वे नौकरी मांगने वाले की अपेक्षा नौकरी देने वाले बनें। हमारा लक्ष्य वर्ष 2023–24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं

को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

उन्होंने कहा कि विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है। लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है।

विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए गये। अब तक 26 हजार 895 युवाओं के पासपोर्ट बनाये गये। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले, जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और उनमें नैतिक गुणों का समावेश करे। इसी दिशा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। हमने नई शिक्षा नीति के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल से जोड़ा है।

उन्होंने युवाओं को आधुनिक रोजगारपरक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है।

हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 100 घण्टे का मानद काम देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई जा रही है। इसके तहत लगभग 4 लाख युवाओं को मानद कार्य उपलब्ध करवाया गया है।

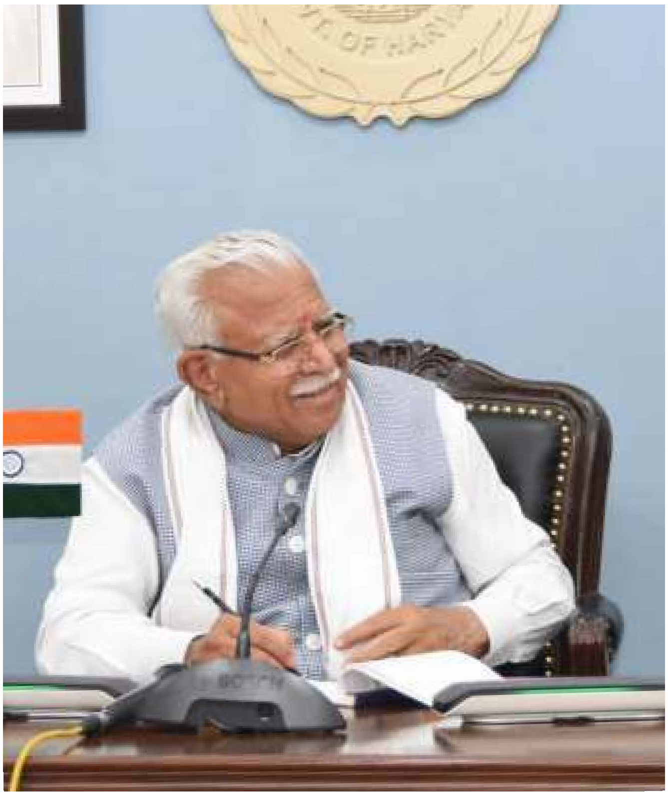

राधा स्वामी व्यास सिरसा सत्संग में शिरकत करना

(दिनांक 29.10.2023)

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा के गांव सिकंदरपुर स्थित डेरा ब्यास में और साध संगत के साथ बैठकर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो की शब्दवाणी सुनी। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो के निवास स्थान पर जाकर उनसे मुलाकात की तथा उन्हें शॉल भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा के रेडक्रोस भवन में बनने वाले नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की जमीन का निरीक्षण किया और उपायुक्त पार्थ गुप्ता को आवश्यक निर्देश दिये।

इसके बाद सिरसा में बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करते हुए कहा कि सिरसा बाबा सरसाई नाथ के नाम पर बसा हुआ है। **इसलिए माननीय मुख्यमंत्री**

जी ने सिरसा बनने वाले मेडिकल का कॉलेज का नाम बाबा सरसाई नाथ के नाम पर करने की घोषणा की। मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की मंजूरी सरकार द्वारा दी जा चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि आसपास के लोगों को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो सके।

इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी नशा मुक्ति सुधार गृह पहुँचे और सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाक़ात की। मौक़े पर ही विशेषकर नशा मुक्ति को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। **उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए**

कहा कि नशे के खिलाफ़ स्पेशल अभियान चलाकर दोषियों पर कानूनी कारवाई की जाए ताकि नशा को जड़मूल से खत्म किया जा सके। उन्होंने स्टेट बॉर्डर पर नशा तस्करी को लेकर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि कोई भी अवैध तस्कर बार्डर से प्रवेश न कर सके।

सिरसा की ऑटो मार्केट का औचक निरीक्षण

(दिनांक 29.10.2023)

प्रभावः माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरसा की ऑटो मार्केट का औचक निरीक्षण किया तथा इसके उपरांत दुकानदारों की समस्याएं सुनी। **माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि 1997–98 में ऑटो मार्केट सिरसा से ली गई 70 लाख रुपये की राशि बैंक ब्याज सहित वापस लौटाई जाएगी तथा ऑटो मार्केट में दुकानें, पैट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, रेस्टोरेंट आदि के लिए निर्धारित भूमि अलाट की जाएगी।** माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि **ऑटो मार्केट में 7 करोड़ की लागत से 210 नई दुकानों का निर्माण करवाकर नीलामी के माध्यम से इन दुकानों को अलाट किया जाएगा।**

साप्ताहिक सूचना पत्र

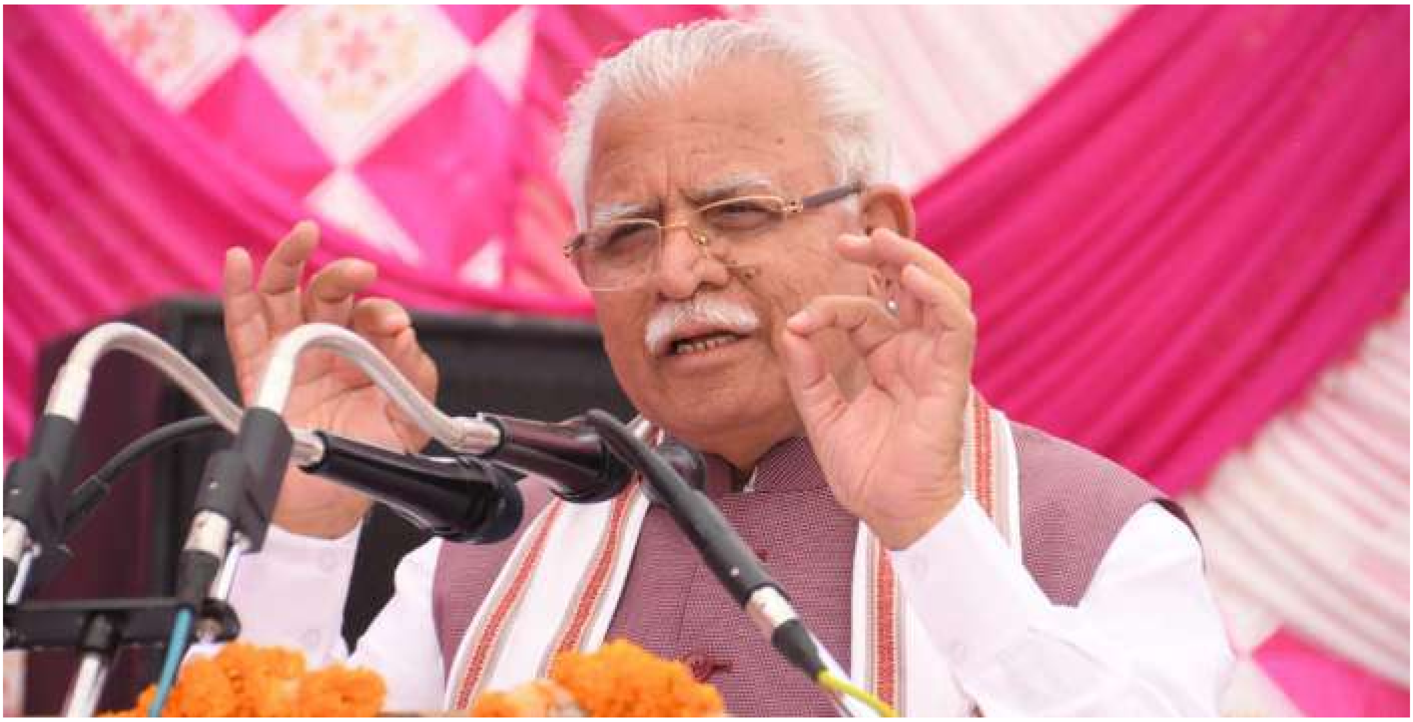

ये दुकानें केवल उन्हीं लोगों को वितरित की जाएंगी जो लोग इसी सेक्टर से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार सही लोगों को दूकानों का लाभ मिलेगा और आटो मार्केट भी पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। इसी प्रकार ऑटो मार्केट में निर्धारित पेट्रोल पंप की ज़मीन पर पेट्रोल पंप लगाने के लिए भी जल्द ही नीलामी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो मार्केट में **नगर परिषद द्वारा लगभग एक एकड भूमि पर 36 दुकानें बनाई गई हैं जिन्हें कलेक्ट्रेट रेट के हिसाब से ऑटो मार्केट को दिया जाएगा।**

इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने थेहड़ से हाउसिंग बोर्ड में विस्थापित 750 से अधिक परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याए भी सुनी। **माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा की कोर्ट के आदेशों के अनुसार जिन परिवारों को पुरातत्व विभाग की जमीन से हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटो में अस्थाई तौर पर बसाया गया था उन्हें जल्द ही सलारपुर गांव में जमीन खरीदकर 100–100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे।**